

**न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)****पीठासीन अधिकारी - पीयूष समारिया (आई.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या 024/2021 (रा.अ.) (GCMS 2021/479)	दायर दिनांक 29.11.2021	निर्णय दिनांक 19.09.2023
--	---------------------------	-----------------------------

**अनवान**

कन्हैयालाल उर्फ काना पिता भैरूलाल उर्फ भेरा जाति जाट उम्र 60 साल निवासी जाफरपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।  
**अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
2. नगर परिषद चित्तौड़गढ़ जरिये अध्यक्ष/आयुक्त नगर परिषद् चित्तौड़गढ़

**प्रत्यर्थीगण**

उपस्थिति :- रतन कुमावत  
भैरूलाल सालवी (राजकीय अधिवक्ता)

अपीलार्थी  
प्रत्यर्थी

**विरुद्ध बनाराजगी एवं निर्णय आदेश दिनांक 26.10.2021 प्रकरण संख्या 660/21 न्यायालय तहसीलदार महोदय चित्तौड़गढ़**

**-:: निर्णय ::-**

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध प्रत्यर्थी के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी का ग्राम जाफरपुरा (वर्तमान ग्राम नाम), पेमाईश पूर्व ग्राम नाम जाफरखेडा पटवार हल्का सेमलिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ में स्थित आराजी नम्बर 1 मीन रकबा 0.48 हैक्टेयर में अपीलार्थी का पुश्तैनी कब्जा पुश्तैनी रूप से चला आ रहा है। उक्त कब्जे काश्त से पुश्तैनी होने से तथा निर्बाद रूप से 70-80 वर्ष का होने से अपीलार्थी ने सरकार के विरुद्ध एवं नगर परिषद चित्तौड़गढ़ के विरुद्ध खातेदारी अधिकार अर्जित कर लिये हैं जो धारा 15 व 19 टीनेन्सी एक्ट के तहत खातेदारी अधिकार अर्जित कर लिये हैं। जिससे अपीलार्थी उक्त आराजियात नियमन से टीनेन्सी काश्त खातेदार के रूप में प्राप्त करने का अधिकारी है। इसलिए तहसीलदार महोदय चित्तौड़गढ़ का बेदखली आदेश विधी विरुद्ध होने से निरस्ती योग्य है। उक्त आराजियात पर अपीलार्थी पुश्तैनी रूप से काबिज होने से अपीलार्थी का उक्त कृषि आराजियात पर व्यवस्थित कब्जा है, जो विगत 70-80 वर्ष पुराना है। इसलिए अपीलार्थी उक्त कृषि आराजियात में नगर परिषद चित्तौड़गढ़ के मुकाबले बेहतर अधिकार रखता है। इसलिए नगर परिषद चित्तौड़गढ़ का आवंटन उक्त कृषि आराजियात पर निष्प्रभावी है। तथा अपीलार्थी का व्यवस्थित कब्जा है। पत्थर कोट के पत्थर पडै है। पत्थर कोट (दीवार) बना रखी है। तथा बीहड के रूप में उपयोग कर



पशु चारा उपज निरन्तर पुश्तैनी रूप से लेता चला आ रहा है। इसलिए अपीलार्थी ने बेहतर पजेशन विरुद्ध नगर परिषद चित्तौड़गढ़ एवं राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय के विरुद्ध अधिकार अर्जित कर लिये होने से अपीलार्थी नियमन का अधिकारी है। इसलिए तहसीलदार महोदय चित्तौड़गढ़ के बेदखली का निर्णय आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में प्रार्थना की गई कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अपीलार्थी को नियमन का अधिकारी घोषित किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के त्रुटिपूर्ण बेदखली आदेश निरस्त फरमाये जावे। एवं पत्रावली नियमन हेतु निर्देशित फरमायी जावें।

इस पर अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। प्रत्यर्थी की और से राजकीय अधिवक्ता हाजिर आये। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। इस पर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/राजस्व/2021/1691 दिनांक 14.12.2021 से से उनकी मूल पत्रावली संख्या 660/2021 निर्णय दिनांक 26.10.2021 अनवानी सरकार बनाम कन्हैयालाल पिता भैरूलाल जाट अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को प्रेषित की गई जो कि रिकार्ड पर होकर पत्रावली के हम किता है। प्रत्यर्थी की और से राजकीय अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दी गई।

दिनांक 19.09.2023 को राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण में सीधे बहस किये जाने का निवेदन किया। इस पर उभयपक्ष की सहमति से स्थगन प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही ड्रॉप कर प्रकरण को सीधे बहस पत्रावली हेतु रखा गया। अपील अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 25.11.2021 को अन्दर मियाद पेश की गई। इस पर उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस अपील को उभयपक्ष सुना गया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अपीलार्थी का ग्राम जाफरपुरा (वर्तमान ग्राम नाम), पेमाईश पूर्व ग्राम नाम जाफरखेडा पटवार हल्का सेमलिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ में स्थित आराजी नम्बर 1 मीन रकबा 0.48 हैक्टेयर में अपीलार्थी का पुश्तैनी कब्जा पुश्तैनी रूप से चला आ रहा है। उक्त कब्जे काश्त से पुश्तैनी होने से तथा निर्बाद रूप से 70-80 वर्ष का होने से अपीलार्थी ने सरकार के विरुद्ध एवं नगर परिषद चित्तौड़गढ़ के विरुद्ध खातेदारी अधिकार अर्जित कर लिये है जो धारा 15 व 19 टीनेन्सी एक्ट के तहत खातेदारी अधिकार अर्जित कर लिये है। जिससे अपीलार्थी उक्त आराजियात नियमन से टीनेन्सी काश्त खातेदार के रूप में प्राप्त करने का अधिकारी है। इसलिए तहसीलदार महोदय चित्तौड़गढ़ का बेदखली आदेश विधी विरुद्ध होने से निरस्ती योग्य है।

इसके जवाब में राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि विवादित आराजियात राजकीय भूमि दर्ज अभिलिखित होकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में नगर विकास न्यास के नाम पर दर्ज रेकार्ड है एवं अपीलार्थी का कब्जा राजकीय भूमि पर होने से नियमन की पात्रता नहीं रखता है, जिससे अपीलार्थी की अपील सारहीन होकर खारीज किये जाने योग्य है। प्रचलित नियमों के अनुसार राजकीय भूमि भूमि आवंटन/नियमन योग्य नहीं है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये।



इसके साथ ही अपीलार्थी द्वारा स्वयं अपने अपील में आराजियात जैरबहस पर अपना अतिक्रमण स्वीकार किया है ऐसी स्थिति में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता है। अतः तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं होने से अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है, एवं प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किये जाने का निवेदन की ईशतदुआ के साथ विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बताया कि उक्त आराजियात पर अपीलार्थी पुश्तैनी रूप से काबिज होने से अपीलार्थी का उक्त कृषि आराजियात पर व्यवस्थित कब्जा है, जो विगत 70-80 वर्ष पुराना है। इसलिए अपीलार्थी उक्त कृषि आराजियात में नगर परिषद चित्तौड़गढ़ के मुकाबले बेहतर अधिकार रखता है। इसलिए नगर परिषद चित्तौड़गढ़ का आवंटन उक्त कृषि आराजियात पर निष्प्रभावी है। तथा अपीलार्थी का व्यवस्थित कब्जा है। पत्थर कोट के पत्थर पड़े हैं। पत्थर कोट (दीवार) बना रखी है। तथा बीहड के रूप में उपयोग कर पशु चारा उपज निरन्तर पुश्तैनी रूप से लेता चला आ रहा है। इसलिए अपीलार्थी ने बेहतर पजेशन विरुद्ध नगर परिषद चित्तौड़गढ़ एवं राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय के विरुद्ध अधिकार अर्जित कर लिये होने से अपीलार्थी नियमन का अधिकारी है। इसलिए तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के बेदखली का निर्णय आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में प्रार्थना की गई कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अपीलार्थी को नियमन का अधिकारी घोषित किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के त्रुटिपूर्ण बेदखली आदेश निरस्त फरमाये जावे एवं पत्रावली नियमन हेतु निर्देशित फरमायी जावे। इसी ईशतदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का बागौर अवलोकन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावलियों का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन कराया। हमने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का अवलोकन किया। अधिनियम में धारा 91 के तहत व्यवस्था की गई है कि :-

**91 Unauthorised occupation of Land -** (1) Any person who occupies or continues to occupy any land without lawful monthly shall be regarded as a trespasser and may be summarily evicted there from by the Tehsildar at any time of his motion or upon the application of a local authority at whose disposal such land has been placed, and 69[any crop standing, or any] building or other construction erected. or anything deposited on such land shall, if not removed with in such reasonable time as the Tehsildar may from time to time fix for the purpose, be liable to be forfeited to the State and to be disposed of 1[in the case of any such crop, in the manner he thinks fit and in other cases] as the Collector may direct:

Provided that the Tehsildar may in lieu of ordering the forfeiture of any such building or other construction, order the demolition of the whole or any part thereof.

1[(2) Such trespasser shall further be liable to pay, for 'each agricultural year during the whole or any part where of has been in such unauthorized occupation of the land, a penalty which may extend to fifty times the annual rent, or assessment, as the case may be, for the first act of trespass. In the case of each subsequent ad of trespass, he



shall by the order of Tehsildar, be liable to commitment to civic person for a term which may extend to three months and to pay penalty to the extent as aforesaid. The amount of such penalty shall be recovered as an arrear of land revenue, and]

1[(3) Where the trespasser ordered to be committed to civil prison under subsection (2) satisfies the Tehsildar by whom he is ordered to be committed to civil prison that he intends to present an appeal, the Tehsildar shall order that such trespasser be released on his own bond for such periods will afford him sufficient time present the appeal and obtain stay order from the Appellate Court and such order shall so long as he is so released on bond be deemed to be suspended]

(4) In any of the following cases, namely.-

(i) where the trespasser does neither vacate the land nor make appearance in response to the notice issue under sub-section (3), or

(ii) where in response to such notice, the trespasser does not vacate the land and makes appearance but-

(a) does not show any such cause, or

(b) makes any representation which is rejected after such inquiry and hearing as may be necessary in the circumstances of the case, the Tehsildar shall, unless, in the case covered by clause (ii) the trespasser under-takes to vacate the land within a week's time- and vacates it within such time order the removal of the trespasser from such land and shall remove or depute any person, to remove him therefrom and take possession thereof; and if the Tehsildar or the person so deputed is opposed or impeded in taking possession of such land, the Tehsildar shall apply to a Magistrate having jurisdiction and such Magistrate shall enforce the surrender of the land to the Tehsildar.

(5) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, the Tehsildar may, in case any such land belongs to the category specified in clause (ii) of the proviso to Section 97, sell it, with the approval of the Sub-Divisional Officer, to the trespasser upon payment by him of the premium therefor at the rate fixed under Section 96 and applicable to such land in addition to the assessment and penalty recoverable from him under sub-section (2) in respect of the whole period of unlawful occupation

1[(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) - (a) whoever occupies any land without lawful authority or, having occupied such land before coming into force of the Rajasthan Land Revenue (Amendment) Act, 1992, fails to remove such occupation within fifteen days from the date of service of a notice in writing calling upon him to do so by the Tehsildar shall, on conviction, be punished with simple imprisonment which shall not be less than one month but which may extend to three years and with fine which may extend to twenty thousand rupees; and

(b) whoever, being an employee of the State Government specifically entrusted by an order of the Collector in writing with the duty to stop or prevent an offence punishable under this sub-section wilfully or knowingly neglects or deliberately omits to stop or prevent such offence, shall, on conviction, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to one thousand rupees or with both :

Provided that, in the case of an offence under clause (a), the court may for any adequate or special reason to be mentioned in the judgment impose a sentence of imprisonment for a term of less than one month :

Provided also that no investigation of an offence under clause (a) of this sub section shall be made by an officer below the rank of a Deputy Superintendent of Police :

Provided further that no court shall take cognizance of an offence under clause (b) except with the previous sanction of the Collector.

अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेखों का गहनता पूर्वक अवलोकन/ परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का मनन किया। भूमि नगर विकास न्यास दर्ज होने से पटवारी हल्का के प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत



कार्यवाही करके बेदखली, शास्ति आरोपण किया गया। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता है। वर्तमान में नगर विकास न्यास दर्ज रिकार्ड है जिस पर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण किया गया एवं अपीलांट द्वारा आराजीयात जैरबहस पर अपना अतिक्रमण होना अपील मेमों में अंकित किया गया है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाकर विधिक निर्णय पारित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा भू-प्रबंध की कार्यवाहियों का तथ्य उठाया गया है। इस संबंध में पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके साथ अपीलार्थी द्वारा इस तथ्य को भी उठाया गया है कि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। इस संबंध में हमारा ठोस अभिमत है कि अपीलार्थी विधि के प्रावधानों के तहत दस्तावेजी साक्ष्य इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता था, किन्तु अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में किसी भी प्रकार से कोई कब्जे के संबंध में कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, ऐसी स्थिति में प्रश्नगत आराजीयात पर अपीलांट का किसी भी प्रकार से हक हिस्सा निहित नहीं होना प्रमाणित पाया जाता है। हमने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से प्राप्त अभिलेख का बागौर अवलोकन, परिशीलन/परीक्षण किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.10.2021 का अवलोकन किया। अपीलांट/अप्राथी को जारी नोटिस का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर नियमानुसार निर्णय पारित किया जाना प्रतीत होता है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.10.2021 विधि सम्मत होकर इसमें किसी प्रकार के संशोधन एवं हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, एवं अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.10.2021 संपुष्ट किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर न्यायालय हाजा में विचाराधीन राजस्व अपील प्रकरण संख्या 024/2021(रा.अ.) अनवानी कन्हैयालाल बनाम सरकार अपील अपीलार्थी गुणावगुण पर बलहीन होकर सारहीन होने से खारीज की जाती है, एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने प्रकरण संख्या 660/2021 निर्णय दिनांक 26.10.2021 अनवानी सरकार बनाम कन्हैयालाल को यथावत रखा जाकर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ निर्णय दिनांक 26.10.2021 की पुष्टि की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 19.09.2023 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पीयूष समारिया)  
जिला कलक्टर,  
चित्तौड़गढ़

